

सतना
21 जुलाई 2024
रविवार



दैनिक

मीडिया ऑडिटर

सतना, रीवा से एक साथ प्रकाशित

जब पुरुष टीम ...
@ पेज 7

कमाई में केसीआर, खर्च में ममता की पार्टी सबसे आगे

20 रीजनल पार्टियों का खर्च आय से ज्यादा, एडीआर की रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की पार्टी गृहमूल कांग्रेस (टीएमसी) खर्च के मामले में देश की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है फाइनैशियल ईंपर 2022-23 में पार्टी की कमाई 333.45 करोड़ रुपए थी, जबकि खर्च 181.1 करोड़ रुपए किए। वहीं, कमाई के मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के, चंद्रशेखर गाव (केसीआर) टॉप पर रही। 2022-23 में पार्टी की कमाई 73.7 करोड़ रुपए रही, जबकि खर्च के मामले में तीसरे और खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर रही। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट्स के



जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वायएसआर कांग्रेस कमाई के मामले में तीसरे और खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर रही। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट्स

(एडीआर) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में देश की 57 में से 39 रीजनल पार्टियों की कमाई और खर्च का व्योग जारी किया है। चानाव आयोग के नियमों के अनुसार, सभी पार्टियों की अपनी सालान आय-व्यय की रिपोर्ट आयोग का सौंपना होती है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनैशियल ईंपर 2022-23 में 39 श्वेती पार्टियों की कुल आय एक हजार 740 करोड़ रुपए थी जो पिछले 2021-22 की तुलना में 20 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं पार्टियों का खर्च केवल 481 करोड़ रुपए ही रहा। यानी कमाई के मुकाबले खर्च कम है।

धारावी पर आक्रमक हुए उद्धव ठाकरे, बोला हमला

कहा-मोदी-शाह की 'लड़का मित्र' योजना मुंबई को अडानी सिटी बनाने की साजिश

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना (यूटीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नंदें मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धारावी की जमीन अडानी के गले में डालकर मुंबई को अडानी सिटी बनाने की साजिश कर रहे हैं। उद्धव ने कहा कि सरकार की लड़का मित्र या लड़का कॉन्स्ट्रक्टर या लड़का डोमोपाति योजना चल रही है। लॉकिन उद्धव ठाकरे ने यह खबर अपनाया कि धारावी के एक भी निवासी को वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। शनिवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव समये आते ही झांटी घोषणाओं की वारिश हो रही है। योजना तब भी शुरू की गई जब लाडली बहन-भाई आदि शुरू हुए।



संक्षिप्त समाचार

केजरीवाल की हेल्थ को लेकर टेंशन में एलजी सक्सेना



नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाई जोड़े में हैं वहीं केजरीवाल की सेहत को लेकर लगातार विवाद जारी है। इस बीच उत्तराखण्ड गढ़ वाले के सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में तिहाई जेल अधिकाकी की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए एलजी की मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर चिंता जारी की है। उन्होंने देश विवादित भोजन और दवाएं न लेने को लेकर सवाल भी उठाया है। एलजी ने कहा है कि मुख्य सचिव इस बात का पता लगाए।

बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा, 105 की मौत

दाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में आरक्षणीय बहाली के सुधीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा जारी है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कार्पूर लगा दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबेदुल कादर ने शुक्रवार देर रात कार्पूर लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंसा



काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। भीड़िया रिपोर्ट्स में बहार गया है कि इसमें 105 लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में बहुत तात्परता वीच अव तक 7/8 भारतीय स्ट्रॉक्स अपने घर लौट आए हैं। दाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बद दिया है।

घाटी पर पाकिस्तान के साथ आया तुर्की दी साइबर आर्मी

अंकारा (एजेंसी)। तुर्की की सरकार ने भारत को हथियार निर्यात पर प्रतिवध लगा दिया है। इसे लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया है। लेकिन जब भी तुर्की की कोई कांग्रेसी भारत से जुड़े ग्राहक को हथियार बेचना चाहती है तब-तब एदमन की सरकार मंजूरी नहीं देती। तुर्की सरकार के एक अधिकारी ने संसद के



सामने यह खुलासा किया। अधिकारी ने बताया कि जब भी एक ग्राहक भारत से जुड़ा होता है तो किसी भी छोटे पार्टी का अपूर्व नहीं दिया जाता है। पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए तुर्की ऐसा कर रहा है। पिछले एक दशक में तुर्की और भारत के सर्वथा में खटास देखी जा रही है तुर्की का पाकिस्तान की ओर झुकाव बढ़ा है तुर्की पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए तैयार है।

यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा

पिछले साल अध्यक्ष बने थे, 5 साल का कार्यकाल बाकी था

मनोज सोनी बोले- इसका पूजा खेडकर विवाद से संबंध नहीं



रूप में शपथ ली थी। इस्तीफे की जानकारी आने के बाद मनोज सोनी ने कहा है कि उनका इस्तीफा देनी आईएससी पूजा खेडकर के विवादों और आरपाण से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। वहीं, कांग्रेस लीडर और राजसभा सांसद जयराम रमेश ने चेयरमैन के द्वारीके पर कहा है कि उन्हें एनटीए से जुड़े विवादों के बीच पद से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक लगातार सर्वधारिक बॉडी की शुचिता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

नीट यूजी का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी

18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश, अगली सुनवाई 22 को

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल ट्रेस्टिंग एजेंसी यानी एनली ने 20 जुलाई को नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें कैंडिडेट्स की पहलान जाहिर हीं रही है। 18 जुलाई को नीट यूजी एग्जाम की सामान्य सुप्रीम कोर्ट में दुई थी। कॉर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि नीट कैंडिडेट्स के रिजल्ट अपलोड करें। कॉर्ट ने कहा था- रिजल्ट अपलोड करें वकल उमीदवारों की पहचान जाहिर ना की जाए। हम सोमवार 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे। ताकि दोपहर तक हम निष्काल निकाल सकें। हम विवर पुलिस रिपोर्ट की एक कांपी भी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समवार तक काउंसिलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार किया था। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुम्हार मेहता ने कहा था- काउंसिलिंग में कुछ समय लगेगा। यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी। सीज़ेआई ने कहा- हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे।

आतंकियों की मौजूदगी का शक, जम्मू में सख्त हुई सुरक्षा

500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात, 50-55 पाकिस्तानी आतंकी कर रहे साजिश



नई दिल्ली/श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 स्पेशल पैरा कमांडो को तैनात किया है। रक्षा मंत्री ने न्यूज एजेंसी को बताया कि जम्मू रीजन में आक्रमणों के लिए दो ट्रेटर एपिट्रिव करने के लिए दुसरे हैं। सेना को इससे जुड़े इंटीलीजेंस इन्स्ट्रुमेंट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा सभाल लिया है। इंटीलीजेंस एपिस्यो भी आतंकियों का समर्थन करने वाले ओवरआर्ट वर्कर्स और इफ्रास्ट्रक्चर को खम्ब करने के लिए काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के मुताबिक, जम्मू में घुसपैठ कर रहे आतंकी हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर कर रहे हैं।

उन्हें एक अधिकारी है। सेना इन आतंकियों की तत्त्वात् और उन्हें खम्ब करने की रणनीति पर काम कर रही है। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सेना पहले ही 3500 से 4000 सैनिकों की अपनी ट्रेनिंग लिया है। इन्होंने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। आतंकियों के बारे में घुसपैठ कर रहे थे, अब उन्हें गांवों में ही हथियार, गोली बारूद और खाना-पीना दें रहे हैं। बोते दिनों जिन 25 सैरियों के

द्विसत में लिया गया था, उन्होंने पूछनाल में इसके सूराग दिये हैं। यह नेटवर्क जम्मू के 10 में से नौ जिलों राजौरी, पूँछ, रियासी, ऊद्हमपुर, कठुआ, डोडा, किरतवाल, जम्मू और रामबन में जम चुका है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व डोडीजीपी एसपी वैद्य के मुताबिक, आटिकल 370 हटने के बाद से ही

વિચાર

मंत्री जी और सरकार की नीट-24 परीक्षा

मैडीकल प्रवेश परीक्षा का मामला इस बार जहाँ पहुंचा है उसमें साफ लगता है कि देश भर के बच्चे और अभिभावक तथा सुप्रीम कोर्ट इसे किसी साफ नहीं जानती होगी, लेकिन वह एक बार में अपनी शक्ति का उपयोग करके अफरातफरी मचाना नहीं चाहती होगी। सो उसने कई तरह के सवाल इस परीक्षा का संचालन करने वाली नैशनल टैस्मिंटंग एजेंसी (एन.टी.ए.) और सरकार के सामने रखे और यह प्रयास भी किया कि सारे बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठाने या व्यवस्था को ज्यादा परेशान किए बिना कछु 'लोकल आप्रेशन' से बीमारी ठीक हो जाए तो वह भी किया जाए। पहले उसने काऊंसेंड्क्षलग रोकने पर बांदिश नहीं लगाने का फैसला दिया था। पर इन सारी कोशिशों में चालीस दिन से ज्यादा का कीमती समय निकल चुका है। कीमती इसलिए कि अब तक बच्चों की काऊंसेंड्क्षलग और नामांकन का काम पूरा हो चुका होता और कई जगह पढ़ाई भी शुरू हो जाती। दैरी की शुद्ध वजह केंद्र सरकार और उसकी इस एजेंसी एन.टी.ए. द्वारा की जारी शरारत है। शरारत ही कहना ज्यादा उचित है क्योंकि इन दोनों का व्यवहार ऐसा है जैसे इनको पता ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ और परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। पेपर लीक की कथा तो परीक्षा की तारीख से पहले ही शुरू हुई और दिन-ब-दिन नए साक्ष्य और अपराधी सामने आते जाने से इसकी व्यापकता, भयावहता और इसमें शामिल लोगों की ताकत का रहस्य खुलता जा रहा है। जब लीक कराने के खेल के छुट्टें भैये पोस्ट डेटेड चैक से भुगतान लेने जैसे व्यवहार चला रहे थे तब उनकी पहुंच, दुन्साहस और ऊपर से कनैक्शन के बारे में सहज ही सोचा जा सकता है। यह तो भला हो बिहार पुलिस के एक जुनूनी अधिकारी का जिसने जान जोखिम में डालकर इस पूरे घट्यंत्रकारी नैटवर्क को नंगा दिखाने की शुरूआत की। हम देख रहे हैं कि रोज नई गिरफ्तारियां हो रही हैं और रोज नए साक्ष्य मिल रहे हैं। अभी ही जो तस्वीर उभर रही है वह कई-कई राज्यों में 50 से 100 करोड़ रुपए तक के लेन-देन की ओर इशारा करती है। और यह संबंधों या विचारधारा के आधार पर कुछ बच्चे-बच्चियों को 'फेवर' करने की जगह एक धंधे के रूप में, वाष्क कमाई के अवसर के रूप में सामने आ चुका है। और जिस तरह से सरकार, मानव संसाधन मंत्री और एन.टी.ए. ने पहले दिन से इस मामले में आचरण किया है वह बताता है कि वे न तो इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, न अपना दोष या चूक मानने को तैयार हैं और न ही आगे से ऐसी गलती न हो। इसका इंतजाम करना चाहते हैं। मंत्री महोदय तो पहले दिन से पेपर लीक न होने का तमगा बांटने में लग गए थे। जो एकमात्र कार्रवाई हुई है वह एन.टी.ए. के प्रमुख का तबादला है-उनको भी किसी तरह की सजा नहीं मिली है। ये वही सज्जन हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में व्यापक करवाने का अनुभव है और आज भी उस मामले में कछु नहीं हुआ है जबकि उसे सामने लाने वाले कितने ही लागू मारे जा चुके हैं। जब मंत्री जी पेपर लीक मानने लगे तो उनका मंत्रालय और एन.टी.ए. इसे सीमित लीक बताने में लगा है। और जगह तो नहीं लेकिन अदालत में सरकार और एन.टी.ए. की तरफ से दी जाने वाली दलीलें उनकी मंशा का सबसे अच्छा प्रमाण हैं। लगता ही नहीं कि इतना बड़ा अपराध हआ है।

रेल दुर्घटनाओं से उपजते सवालों के जवाब आखिर कौन देगा, कब तक मिलेगा

कमलेश पांडे

लीजिए, एक और ट्रेन दुर्घटना हो गई। यह घटना उत्तरप्रदेश के गोंडा ज़िले में हटित हुई, इसलिए इसे गोंडा ट्रेन दुर्घटना के नाम से जाना गया। देखा जाए तो पिछले एक महीने में यह दूसरा बड़ा रेल हादसा है, जिसमें 3-4 यात्रियों की मौत हो चुकी है और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल चुके हैं। इससे एक सुलगता हुआ सवाल पैदा हो रहा है कि लाखों लोगों के लिए यात्रा का प्राथमिक साधन रेलवे अब उतना सुरक्षित नहीं रह गया है, जितनी कि उससे अपेक्षा हुआ करती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के रेलवे नेटवर्क में, 64,000 किलोमीटर (40,000 मील) ट्रैक पर 14,000 ट्रेनों में प्रतिदिन 12 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। बावजूद इसके यहां रेल दुर्घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। गत जून महीने में ही पश्चिम बंगाल में एक मालगाड़ी एक यात्री ट्रेन से टकरा गई, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए, क्योंकि मालगाड़ी के चालक ने सिग्नल की अनदेखी की थी।



इसा तरह से पञ्चल साल, पूवा भारत में एक बड़ा ट्रून दुर्घटना हुई, जिसमें 280 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जो दशकों में सबसे बातक दुर्घटनाओं में से एक थी। आलम यह है कि रेल सुरक्षा में सुधार के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद, हर साल कई एक दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनका कारण अक्सर मानवीय भूल या पुराने सिस्टम्स उपकरण होते हैं। लेकिन लगातार हो रही इन रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण सवाल पैदा हो रहे हैं, जिनके जवाब समय रहते ही मिल जाएं तो इन दुर्घटनाओं को टाला जा सकेगा। पहला, रेलवे की %कवच% सुरक्षा प्रणाली अब तक केवल 1 प्रतिशत रेलवे ट्रैक को ही क्यों कवर कर पाई है? इस विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरा, अगर देश के पास सभी रेलवे ट्रैक पर कवच प्रणाली लगाने के साधन नहीं हैं, तो प्रधानमंत्री और रेलमंत्री कवच प्रणाली को अपग्रेड करने के बजाय बुलेट ट्रेनों और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या उनके ऊपर कोई कूटनीतिक दबाव है या फिर मित्र उद्योगपतियों और टेकेदारों को उपकृत करने के लिए यह सबकुछ किया जाएगा। तीसरा, लगातार रेल दुर्घटनाओं के बावजूद भारत सरकार ने रेल सुरक्षा पर खर्च करने के बजाय बुलेट ट्रेनों पर 1 लाख करोड़ रुपये क्यों खर्च किए? क्या इसके लिए रेलवे सुरक्षा के लिए आवंटित धन को डायर्वर्ट किया गया? चतुर्थ, वित्त वर्ष 2024 में ट्रैक नवीनीकरण के लिए आवंटन बजट के 7.2 प्रतिशत तक ही सीमित क्यों रखा गया? क्या सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए रखरखाव और नवीनीकरण को उच्च प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए? यदि नहीं तो फिर उपाय क्या है? पंचम, दिसंबर 2022 में सीईजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2018 से 2021 तक 69

प्रातःशत रेल दुर्घटनाएँ रेल दुर्घटनाओं से सबाधूत था। साएजा निरीक्षण रिपोर्ट में गम्भीर कमियों की पहचान की गई थी। लेकिन उन कमियों पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? छठा, रेलवे में लगभग 3 लाख रिकियाँ क्यों हैं? जिनमें से 1.5 लाख से अधिक सुरक्षा से संबंधित पद हैं। क्या इस सरकार के लिए यात्री सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है? या फिर इसे भी चरणबद्ध रूप से निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी चल रही है, जो समय के साथ प्रकाश में आएंगा। सातवां, लगातार दुर्घटनाओं के बावजूद मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में क्यों मिला दिया? क्या इसे उचित फैसला करार दिया जा सकता है। आठवां, जब कतिपय जांच रिपोर्ट में दुर्घटनाएँ के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल की विफलता, संचालन के प्रबंधन में कई स्तरों पर खामियाँ और लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के पास वॉकी-टॉकी जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता जैसे कुछ कारण बताए गए हैं, तो फिर उन्हें पूरा करके इन कमियों को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? नवम, इन तमाम गम्भीर सवालों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो आत्म-प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ते, सेल्फी और रील कल्चर के आदि हो चुके हैं, को भारतीय रेलवे में हुई भारी खामियों की सीधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? दशम, सच कहा जाए तो यह जांच का विषय है कि ट्रेन से जुड़ी कई दुर्घटनाएँ लगातार हो रही हैं, पर अपेक्षित कार्रवाई नदारत। देश में लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, लोगों अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो वो रेल मंत्री हैं या फिर रेल महकमें के वो बड़े अधिकारी जो इन्हें रोकने के प्रति गम्भीर नहीं हैं। इसलिए

पूर्व के रेल मंत्रियों की तरह ही इन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अंतिम सवाल यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? वैसे तो पिछले दशक में भारत में कई रेल दुर्घटनाएँ कई कारणों से हुई हैं, जिनमें यांत्रिक विफलताओं से लेकर मानवीय लापरवाही तक शामिल हैं। इसलिए यहाँ पर हम कुछ प्रमुख घटनाओं, उनके कारणों और अधिकारियों द्वारा कही गई बातों पर एक नज़र डालते हैं, ताकि आप यह समझ सकें। पहला, 26 मई, 2014 को, हिसार-गोरखपुर मार्ग पर गोरखधाम एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में एक डबल-लाइन सेक्षन से गुज़र रही थी, जब इसका इंजन 11 डिब्बों के साथ पटरी से उत्तर गया। इस दुर्घटना का कारण टंग रेल का फ़ैक्टर माना गया, जो ट्रेनों को आसानी से दूसरी रेलवे लाइन पर जाने में मदद करता है, और इसे उपकरण की विफलता के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस घटना में कम से कम 29 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दूसरा, 2015 में वाराणसी-देहरादून जनता एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के एक स्टेशन पर रुकने में विफल रही, जिसके कारण 20 मार्च, 2015 को कुछ डिब्बे दुर्घटनाग्रस्त हो गए और पटरी से उत्तर गए। उस समय रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा था कि जब ट्रेन बछरावां स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, तब ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को पार कर लिया और रेत के ढेर में जाटकराई, जिससे ट्रेन का इंजन और दो डिब्बे पटरी से उत्तर गए। इस घटना में लगभग 39 यात्रियों की मौत हो गई और 150 लोग घायल हो गए। तीसरा, 20 नवंबर, 2016 को कानपुर देहात जिले के पुखरायां इलाके में इंदौर-पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उत्तर गए। इस दुर्घटना में 152 लोगों की जान चली गई। हाल के वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई सबसे बड़ी मौतों में से यह एक है। चतुर्थ, 21 जनवरी, 2017 को जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखण्ड एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के कुनेरु स्टेशन पर पटरी से उत्तर गई। ओडिशा जाने वाली इस ट्रेन की दुर्घटना में 40 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पंचम, 19 अक्टूबर, 2018 को अमृतसर के नजदीकी रेलवे ट्रैक पर दशहरा समारोह देखने के लिए खड़े लोगों को दो ट्रेनों ने रोंद दिया, जिसमें लगभग 60 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। जब जालंधर-अमृतसर डीएमयू ट्रैक पर आई, तो आतिशबाजी देखने के लिए लगभग 300 लोगों की भीड़ जमा थी। छठा, 3 फरवरी, 2019 को बिहार के वैशाली जिले में दिल्ली जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस की बोगियों के पटरी से उत्तरने के कारण सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना में सहदई-बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के पास नौ ट्रेन के डिब्बे पटरी से उत्तर गए। सातवां, हैदराबाद के पास चेरलापल्ली स्टेशन से नासिक के पनेवाड़ी स्टेशन जा रही एक खाली मालगाड़ी ने 8 मई, 2020 को पटरियों पर सो रहे 16 श्रमिकों को गलती से कुचल दिया। कथित तौर पर लोको पायलट ने श्रमिकों को देखा, लेकिन समय रहते ट्रेन को रोकने में विफल रहा। आठवां, 13 जनवरी, 2022 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के डोमोहानी इलाके में बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उत्तर जाने से 10 यात्रियों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीआरएस के अनुसार, पटरी से उत्तरने का कारण उपकरण (लोकोमोटिव) की विफलता थी। नवम, 2 जून 2023 को शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, बंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी परस्पर टक्कर हुई। इन तीनों ट्रेनों की टक्कर के कारण भारत में सबसे खराब रेल दुर्घटना हुई, जिसके कारण 2 जून, 2023 को कम से कम 293 लोगों की मौत हो गई। दशम, इस साल 7 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और कम से कम 40 लोग घायल हो गए। बहरहाल, सरकार ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जो नाकाफ़ी है। मृतकों के परिवारों को कम से कम ₹50-50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

छम एवं पारिवर्णी बालाओं से मुक्ति की सार्थक पहल

ललित गर्ग

भारतीय हिंदू संतों की प्रमुख संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) की ओर से चौदह महामण्डले श्वरों और संतों के निष्कासन की ताजा कार्रवाई पाखण्डी एवं छद्य बाबाओं से समाज को मुक्त करने का सराहनीय कदम है। अखाड़ा परिषद की गोपनीय जांच में अखाड़ों से जुड़े ये संत धार्मिक कार्यों के बजाय धनार्जन एवं अधार्मिक कार्यों में लिप्त पाए गए। ऐसे ही अन्य बाबाओं पर व्यभिचार, दुष्कर्म, जादू-टोटके व दूसरे अनैतिक कार्यों के भी आरोप लगते रहे हैं। इनके अलावा सौ से अधिक संतों को अखाड़ा परिषद ने नोटिस भी दिया है। निष्कासित किए गए संतों को अगले साल होने वाले कुंभ में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। अखाड़ा परिषद की ताजा कार्रवाई इस तरह के कथित धर्मगुरुओं पर लगाम लगाने की प्रभावी कोशिश मानी जाएगी। इस तरह के प्रयास हर स्तर पर होने चाहिए, ताकि छद्य एवं पाखण्डी धर्मगुरुओं से समाज को मुक्ति मिल सके। आम लोगों में भी विवेक का जागरण जरूरी है, ताकि धर्म को विकृत करने वाली ऐसी घटनाओं को नियन्त्रित किया जा सके। अखाड़ा परिषद ने कुल चौदह ढोंगी संतों की एक सूची मैटिड्या में जारी की है। सूची में जेल की हवा खा रहे बाबा रामपाल, गुरमीत राम रहीम सिंह इंसां, आसाराम, नारायण साई व असीमानंद के अलावा निर्मल बाबा, राधे मां और कई ऐसे इच्छाधारी बाबा शामिल हैं, जो पिछले कुछ सालों में अपनी करनी के चलते विवादों में रहे हैं। गोलगप्पा खिलाकर लोगों की हर समस्या का समाधान करने वाले निर्मल बाबा जैसे ढोंगियों के झांसे में लोग कैसे खिंचे चले आते हैं, इस पर भी अखाड़े की ओर से कई चाँकने वाले तथ्य बताए गए हैं। उनका मानना है कि राधे मां और निर्मल बाबा जादू-टोटके से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। बाबाओं की कारस्तानियों ने सबको सकते में डाल रखा है। महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करना इन बाबाओं की दिनचर्याओं में शामिल था। लाज-शर्म की वजह से कुछ महिलाएं नहीं बोलती थीं, उन्हीं का ये बाबा फायदा उठाते थे। इन बढ़ती त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों के खिलाफ अब पूरा अखाड़ा



परिषद मुखर हो उठा है। जरूरत है ऐसे ही अन्य शीर्ष धर्म संगठनों के सक्रिय होकर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाई करने की। फर्जी एवं पाखण्डी बाबाओं के मामले में भोले-भाले एवं अशिक्षित लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और जिन बाबाओं ने ये कुर्कम किया है, उन्हें ढंगकर दंड देना ही चाहिए। फर्जी एवं पाखण्डी बाबाओं की परंपरा सदैव से दुष्टों के हाथ में रही है। इसका आरंभ किया था महाभारत में शकुनि ने। हमारे समाज एवं राष्ट्र ऐसे बहुत सारे बाबा रूपी शकुनि हैं, जिन्हें हम समय पर पहचान नहीं पाते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच जब जुए का खेल हुआ, तो शर्त यही थी कि पांसे शकुनि चलेगा। शकुनि ने पांसे भी ऐसे तैयार किए थे कि उसको परिणाम और प्रश्न मालूम थे। आधुनिक बाबा भी ऐसे ही पांसे चलते हुए हुए कइयों की जिंदगी

